Drive was also undertaken by Public Sector Undertakings, Banks and Insurance Corporations. As against a backlog of 15195, 8960 candidates were offered appointment.

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शों की अवहेलना

1613. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शों की अवहेलना की गई है ; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट आल्वा (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें संघ लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की	असहमति के मामलों की कुल संख्या
1986–87	17533	30
1987–88	16389	22
1988–89	14705	15
1989–90	14740	10
1990–91	19024	8

(ख) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के मुख्य कारण ये हैं (i) सेवा रिकार्डों के आधार पर उम्मीदवार की उपयुक्तता के मूल्यांकन में विचारों में मतभेद तथा अन्य संबंधित पहलू (ii) कदाचार के लिए उपयुक्त सजा के संबंध में विचारों में मतभेद।

Problem of Redundent Officers

1614. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily 'Hindu', dated the 23rd May, 1992 under the caption "The problem of redundant Officers" and if so, the number of officers sent back to States; and

(b) whether the State Government have represented that the allotment of I.A.S. Officers to States must be reduced and if so, the steps taken to ease the burden of States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The Government is aware of the news item published in the daily 'Hindu' dated 23rd May, 1992 under the caption "The great Delhi Axe and after" which *inter alia* relates to problems of redundant officers. No officer serving at the Centre

has been sent back to his parent Cadre/State consequent upon the abolition/surrender of any post. Only those officers who have completed their normal tenures at the Centre or have been recalled by their respective cadres have been reverted to their respective State Cadres.

(b) The mode of determination of vacancies, state-wise, is through consultation with State Government. Some State Government have suggested a reduction in the intake of I.A.S. Officers. The number of I.A.S. Officers to be recruited through Civil Services Examination, 1991 has been marginally reduced.

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गए लक्ष्य

1615. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का समुचित कार्यान्वयन न किये जाने के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री जी० वेंकट स्वामी : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) जो कि गुजरात सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था, का वर्ष 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) नामक एक नए कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है । योजना के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी सृजित किए गए रोजगार के श्रम दिनों के रूप में की जाती है । वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए निर्धारित 244.25 लाख श्रम दिनों के रोजगार सृजन के लक्ष्य की तुलना में 254.13 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया है । चूंकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है इसलिए उपचारी कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1991-92 की अवधि के दौरान गुजरात में जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग और योजना का समुचित कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

Godowns in Andhra Pradesh

1616. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of godowns sanctioned and completed in Andhra Pradesh under the "Scheme for setting up of Rural Godowns" and what was central assistance provided so far; and

(b) what is the target for the year 1992-93 in Andhra Pradesh under this scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) 446 rural godowns with a total storage capacity of 2.77 lakhs tonnes have been sanctioned in Andhra Pradesh under the 'Scheme for Setting up of Rural Godowns' so far. An amount of Rs. 3.60 crores has been released as central assistance for the purpose. Out of 446 godowns, construction of 246 godowns with a total storage capacity of 1.68 lakhs tonnes has been completed and the remaining godowns are at different stages of construction.

(b) The scheme stands transferred to State Sector with effect from 1-4-1992 alongwith a large number of schemes as part of the general policy decision of the Government.